बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

सोमवार, तिथि 26 मार्च, 1984

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार, तिथि 26 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(सदन में शोरगुल)।

अध्यक्ष—शांति, शांति। जो भी अहम विषय आप उठाना चाहते हैं उसके लिये समय निर्धारित है। आप जो विषय उठाना चाहते हैं कोई अहम-से-अहम विषय, तो उसके लिये कायदा है, लेकिन यह निर्णय करके आये हों कि हम सदन को नहीं चलने देंगे, तो यह दूसरी बात है। विषय को उठाने के लिये हमारे यहां स्थगन प्रस्ताव दिया जाता है, शून्य काल के लिये विषय यह निश्चित है, ध्यानाकर्षण का विषय निश्चित है।

(सदन में शोरगुल)।

शांति, शांति। एक-एक का निष्पादन होगा जब समय आयेगा तो और उस समय जो कहना होगा कहियेगा लेकिन इस तरह से कीजियेगा तो हाउस का बिजनेस नहीं चल सकता है।

(सदन में शोरगुल)।

श्री जयकुमार पालित—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि आपने कहा कि सभी चीजों के निष्पादन का समय है तो यह शून्यकाल है और यह मैटर शून्यकाल का ही है। इतना अरजेन्ट और अहम मैटर है इसलिये इसको पहले लिया जाय।

1983 द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त 85,000 (पचासी हजार) रु० अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव राज्य पाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदानों तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राज्य विधान-मंडल" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विधान-मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 1983 द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त 85,000 (पचासी हजार) रु० अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंत्रि-परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए मंत्रि-परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विधान-मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 1983 द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त 1,67,32,085 (एक करोड़, सरसठ लाख, बत्तीस हजार, पचासी) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष—कटौती 3 से 8 श्री राजकुमार पूर्वे, उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, राम विलास मिश्र, राजमंगल मिश्र, राम लषण राम "रमण" तथा मु० इलियास हुसैन हैं।

कटौती प्रस्ताव

इस मांग के औचित्य पर विचार-विमर्श।

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाय।"

इस मांग के औचित्य पर विचार-विमर्श करने के लिए।

अध्यक्ष—आज पाँच बजे तक वाद-विवाद चलेगा। साढ़े चार बजे से सरकार का जवाब है। आज बहुत से डिमांड्स हैं, इसलिए बोलते समय इस पर भी ख्याल रखेंगे।

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, अभी द्वितीय अनुपूरक व्ययक में जो मांग की कटौती के लिए प्रस्ताव दिया है वह मांग मुख्यत: सामान्य प्रसाशन से सम्बन्धित है। ये जो रुपया ले रहे हैं वह किस चीज के लिए ले रहे हैं? इनका मेन बजट था 24 अरब 15 करोड़ का, प्रथम सप्लिमेंटरी 6 अरब का और द्वितीय सप्लिमेंटरी 3 अरब का है। यानी मुख्य बजट का आधार इस प्रकार ले रहे हैं जिस पर कोई डिसकशन नहीं होता है हाउस में। बजट का हर डिमान्ड हाउस में डिसकस होना चाहिये वह नहीं होता है। अगर हाउस को अवहेलना कर आधा बजट इस प्रकार से पास कर दिया जाए तो क्या इससे डिमोक्रेसी का मखौल उड़ाना नहीं होता है? दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बजट बनाने के पहले आपके ब्यूरोक्रेसी को इसका अनुमान रखना चाहिये, हर पार्टी से आपकी पार्टी के अधिक सदस्य हैं उनसे राय लेकर प्रोडक्टिव योजनाओं पर खर्च करने के लिए राशि का आबंटन करें, ननप्रोडक्टिव खर्च पर अधिक पैसा न खर्च हो इसका पूर्वानुमान करना चाहिये। अगर प्रोडक्टिव पर आधारित आप इसे करेंगे तो बिहार के डेवेलपमेंट का रेट बढ़ेगा लेकिन यह जो सप्लिमेंटरी बजट रखा गया है वह क्या है? 3 अरब आप खर्च किये हैं, पदाधिकारियों के जीवन यापन भत्ते पर 4 हजार अतिथिशाला में भोजन के लिए 5 लाख 25 हजार का खर्च दिखाया गया है। अतिथिशाला में भोजन के लिए वह भी बाहर का नहीं राज्य के अतिथिशाला के लिए। कर्मचारियों को केन्द्रीय दर पर भत्ता और बेतिया के उपचुनाव के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय में तो दिया है, द्वितीय अनुपूरक व्यय में भी आधा करोड़ खर्च दिखाया गया है। 123 विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का गहन पुनरीक्षण हुआ है 22 अक्टूबर से जिसमें 76.41 लाख खर्च ले रहे हैं। इसके बाद 1980 में जो चुनाव हुआ है उसके भुगतान के लिए 23 लाख प्रथम अनुपूरक में आप ले चुके हैं और इसके बाद द्वितीय अनुपूरक में लिये हैं। 1980 का भुगतान आप 4 वर्ष बाद कर रहे हैं जिसके लिए प्रथम अनुपूरक में आप ले चुके हैं और इससे पेट नहीं भरा तो द्वितीय अनुपूरक में ले रहे हैं। इसके बाद सचेतकों की नियुक्ति के कारण 1 लाख रुपये प्रथम अनुपूरक में लिये हैं और द्वितीय सप्लिमेंटरी में 1 लाख 35 हजार ले रहे हैं। चन्द्रशेखर बाबू मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा है कि इतने 19 सचेतक हों और फिर 15 के लिए पी० ए० वगैरह के लिए मांगते हैं, यह क्या इकोनोमी कांइसेप्शन नहीं है?

आप 19 सचेतक बहाल कर रहे हैं, पी० ए० को 250 रुपया देते हैं। इसके लिए डिमांड पास कराना चाहते हैं।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

वित्त विभाग लेखा सम्बन्धी मामले पर गैर-सरकारी सदस्यों के लिए विमर्श हेतु यात्रा भत्ता का 8 लाख रुपया समाप्त हो गया है और 3 लाख रुपया और आप मांग रहे हैं। यही है आपका 20-सूत्री कार्यक्रम ? उसी तरह से देखिये 20-सूत्री के अध्यक्ष के निजी सहायकों के लिए आपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री में भी रुपया लिया और इसमें भी आप 1 लाख 15 हजार रुपया ले रहे हैं। पटना जिला कार्यालय के उपबंध में खर्च करने के लिए आप 1 लाख रुपया ले रहे हैं। नवसृजित प्रमण्डल संथाल परगना के कार्यालय में खर्च करने के लिए और स्टाफ कार के लिए आप ढ़ाई लाख रुपया ले रहे हैं। प्रमण्डलों के 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2.65 लाख रुपया ले रहे हैं। उसी तरह से आपका भोजशाला का भी उपबन्ध समाप्त हो गया है जिसके लिए आप दो लाख एक हजार रुपया ले रहे हैं। इस तरह से आप भोजन के लिए, टी० ए० के लिए, सचेतकों के लिए लाखों रुपया मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार की जनता को कहेंगे कि आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे इन्टरेस्टिंग बात तो यह है कि दिल्ली स्थित सी० एम० अतिथिशाला को सुसज्जित करने के लिए 1 लाख रुपया आपका घट गया। मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि उसमें कौन-कौन से सामान लगाये गये हैं उसकी लिस्ट दी जाय क्योंकि आप एक कमरे को सुसज्जित करने के लिए एक लाख रुपया ले रहे हैं न कि किसी और चीज के लिए ले रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—एक दिन ठहरने का निमंत्रण हम आपको देते हैं। (हंसी)

श्री राज कुमार पूर्वे—आप इसकी सूची दीजिये कि कौन-कौन से सामान लगाये गये हैं। उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय जो यहां के विकास आयुक्त हैं योजना आयुक्त, दिल्ली से परामर्श करने के लिए गये हैं, तो उनके टी० ए० पर 1 करोड़ 43 लाख रुपया खर्च हुआ है। एक व्यक्ति पर 1 करोड़ 43 लाख रुपया टी० ए० पर खर्च आप करते हैं यही आपका इकोनोमी का कार्यालय है और इसी का सैंक्शन आप हाउस से लेना चाहते हैं, क्या यही विकास के रास्ते पर नये मुख्य मंत्री चल रहे हैं। इसी रास्ते पर चलने के वजह से तो पुराने मुख्य मंत्री गये और अब ये जायेंगे और साथ-साथ कांग्रेसी राज इसबार स्वाहा होने जा रहा है। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊंगा कि

ये कन्टीजेंसी पर कितना रुपया लेते हैं। बिहार में कन्टीजेंसी फण्ड के लिए जो जो अनफोरसीन एक्सपेंडीचर होगा उसके लिए 50 करोड़ रुपया का प्रावधान 1950 में किया गया था। लेकिन बिना कोई ऐक्ट बनाये हुए इसको इन्होंने ओर्डिनेंस के मार्फत 200 करोड़ रुपया कर दिया है जबकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी कन्टीजेंसी, अनफोरसीन एक्सपेंडीचर के लिए 50 करोड़ रुपये का ही प्रावधान है लेकिन बिना कोई ऐक्ट बनाये हुए, आर्डिनेंस के माध्यम से इन्होंने 200 करोड़ रुपया कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, कमरा को सुसज्जित करने के लिए 1 लाख रुपया, एक व्यक्ति के टी० ए० पर खर्च करने के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपया यही हे इनका अनफोरएक्सपेंडीचर जिस पर आप हाउस की अनुमति लेना चाहते हैं। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री ने जो कुछ बातें कही थी उसी पर कन्सन्ट्रेट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उतना समय नहीं है लेकिन वास्तविक रूप से अपने राज्य में विगत दो महीने में जो गोली चली है, आदमी मरे हैं, कितने के साथ रेप हुआ है इन सब की कोपी मेरे पास है उसे मैं मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा कृपा करके वे इनका जवाब दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लहसुना कांड जो हुआ उसके संबध में मुख्य मंत्री ने कहा कि पूर्व जो आप नहीं समझते हैं कि यह कांड दूसरे कंटेक्सट में हुआ है। मैं कहना चाहता चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को लैंड से प्रेम नहीं है चूंकि वे लैंड बेच चुके हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 1984 को "इंडीयन नेशन" में जो निकला है उसको में आपकी इजाजत से पढ़ कर देना चाहता हूं: -

"Youth killed, Harijan, Houses set on fire.

Nawadah, Jan. 21 (UNI) : A 22 year old person was killed and 10 harijan houses were set on fire allegedly by the landlords at Gopalpur in Akbarpur police station area, according to official sourses. Twelve others sustained severe burn injuries and their cattleheads pereished in the fire, the sourses added. Police soures said the incident took place as the Hrijans, whom the Govt. had given land ownership, refused to surrender the land to the landlords.

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि जो जमीन सरकार द्वारा बांटी गयी है उस जमीन पर वह रहना चाहता है और लैंडलोर्डस उसको हटाना चाहते हैं। क्या यही बीस सूत्रों के अंतर्गत लैंड रिफोर्म हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर आपका ध्यान और आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि श्रीमती कृष्णा शाही की जमीन सीवान में

है उस जमीन को तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन राम ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बांटा था। उसका पर्चा भी लोगों को मिला है और फिर भी उस जमीन पर जिन्हें पर्चा मिल चुका है उनको अधिकार नहीं होने दिया जा रहा है। आप उस पर कब्जा दिला दीजिए तो समझेंगे। 1970-71 वाले चन्द्रशेखर सिंह मेरे ख्याल में आप नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चंडी थाना के गदनपुरा, खरजावापुर में डेढ़ सौ एकड़ जमीन है जिस पर से लोगों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। मेरा कहना है कि आप उसकी रक्षा कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी को उस दिन भी लिखकर दिया था कि एक महंथ खजौली थाना में सरकार की जमीन को बेच दिया था जिसकी इंक्वायरी की गई और 420 का मुकदमा बना। मुकदमा तो नहीं चला और भी दूसरी जमीन वह महंथ बेच रहा है। जो जमीन वह बेच रहा है उसे राजस्व आयुक्त ने बांटा था और अब उस जमीन से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अखबार में देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पैसे और पैरवी के दिन अब लद गए। इसके संबध में दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक डा० मिथिलेश कुमार हैं जो कैंसर चिकित्सक के रूप में पहला नाम था। हमारे पास कमीश्नर के नोट की फोटो स्टेट कापी भी है। कमीश्नर ने अपने नोट में लिखा है कि जब-जब उनकी फाइल नोटीफिकेशन होने लगती है तब तक उनकी फाइल को गायब किया जाता है। उनके संबंध में अंतिम रूप से आदेश होता है कि पहले आदमी हैं इनका होना चाहिए मिनिस्टर अपना नोट देकर दस्तखत कर देते हैं और संचिका राज्य मंत्री के माध्यम से आयुक्त के यहां जाता है। पृष्ट 30 पर मिनिस्टर लिखते हैं कि मैं कमिश्नर के नोट से सहमत हूँ। बाद में फाइल कमिश्नर के यहां जाता है तो फाइल राज्यमंत्री मंगा लेते हैं और मिनिस्टर का नोट काट देते हैं और दूसरा नोटशीट लगा कर लिख देते हैं कि पृष्ठ 31 के नोट से सहमत हूँ। फिर मिनिस्टर के यहां फाइल जाती है तो मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा नोट फटा हुआ है। कौन हिम्मत किया है, उसको सजा दी जाय। क्या आपमें हिम्मत है कि उस राज्यमंत्री को सजा दें, मैं आपसे पूछ सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, पालाजोरी में 6 आदिवासियों को मारा गया। वहां के जो डाक्टर हैं उस डाक्टर के बारे में कहा जाता है कि पालाजोरी कांड में उसका हाथ भी है। सुनते हैं कि कमीश्नर और डी० आई० जी० की रिपोर्ट पर सरकार ऐक्ट करती है। सरकार को डी० आई० जी० ने लिखा है कि यह जो आदमी 14 वर्षों से है और राजनीति में लिप्त है इसका ट्रांसफर किया जाय और सजा दी जाय

इस केस के बारे में पुनः कहना चाहता हूँ कि जिसके बारे में अपना एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है और हेल्थ कमीशनर और डी० आई० जी० लिखते हैं कि 6 आदिवासियों की हत्या की गई उसमें इसका हाथ है। जेल भेजना तो दूर रहा उसका ट्रांसफर भी रोके हुये हैं। मैं कहता हूँ कि पैसा और पैरवी अभी भी चल रही है। हिम्मत है तो उस राज्यमंत्री को सजा दें। तो मैं समझूंगा कि पैरवी के दिन लद गया। आपके बारे में तो कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन आपके सामने जो हो रहा है उसको देखिये।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, उपर्युक्त बातों को कहते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए सदन से मांग करता हूँ कि इस खर्च का कोई औचित्य नहीं है इसको नामंजूर किया जाय और फिजूलखर्ची को रोका जाय। क्योंकि बिहार में कोई प्रोडक्टिव योजना नहीं है। बिहार में सबसे कम परकेपिटा इनकम है। सबसे ज्यादा बेकारी है, सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही दूसरे-दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। बंगाल, पंजाब और दिल्ली में जाकर नौकरी करते हैं। ऐसी हालत में इस सरकार के हाथों बिहार सुरक्षित नहीं है। इस सरकार को बने रहने का कोई भी नैतिक औचित्य नहीं है।

श्री जयकुमार पालित : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इसके पहले कि राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं जिसके लिये हमारी सरकार बड़ी उत्सुकता से आगे चलने के लिये बेचैन हैं उसपर सरकार का ध्यान में माननीय सदस्य श्री राजकुमार पूर्वे जो सदन के बहुत हो पुराने माननीय सदस्य हैं के बारे में कहना चाहता हूं। मैं बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। हमें उनसे आशा थी कि वे कुछ सुझाव देंगे और सरकारी खर्च में कमी करने के संबंध में भी कुछ अच्छे सुझाव देंगे लेकिन ऐसा न करके उनका नजर गया है मुख्य मंत्री के कक्ष के सजाने में जो खर्च होगा उसपर उनका नजर गया है नये-नये जिले और अनुमंडल जो बने हैं उसपर होनेवाले खर्च पर उनका नजर गया है। टी० ए० पर खर्च होनेवाली रकम पर लेकिन उनका ध्यान सामाजिक पेंशन की ओर नहीं गया है, उनकी नजर बेरोजगारों को जो तरह-तरह के ऋण देकर रोजगारमुख किया जा रहा है उस ओर नहीं गया। उनकी नजर बूढ़े-बूढ़ियों को जो पेंशन दी जा रही है उस ओर नहीं गया है। स्वनियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगार नौजवानों को जो 25 हजार रुपया देकर रोजगार दिया जा रहा है उस ओर नहीं गया है। पूर्वे जी की नजर उस ओर नहीं गई है जहाँ पिछले साल राज्य में अढ़ाई सौ, तीन सौ तथा साथ

तीन सौ मेगावाट तक बिजली का उत्पादन होता था वहाँ इस साल छः सौ सात सौ तथा साढ़े सात सौ मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करके खेतों तथा उद्योगों को बिजली दिया जा रहा है। इसी बिजली की कमी के चलते पिछले साल खेती और उद्योग दोनों का ह्रास हो रहा था वहाँ इस साल खेती और उद्योग दोनों में वृद्धि हो रही है। आज हर जगह लगातार बिजली मिल रही है।

पूर्वे जी का ध्यान रोहतास में कम्युनिस्ट पार्टी और हिन्द मजदूर सभा की ओर से जो हड़ताल था उसे मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री के प्रयास से समाप्त कराया गया है उस ओर नहीं गया है। वहाँ जो लोग बेरोजगारी के कगार पर खड़े थे उसे फेजवाइज करके खोला जा रहा है वह पूर्वे जी के नजर में नहीं आया। उनकी पार्टी तो जब जैसा मौका होता है करती है कभी हमलोगों के साथ रहती है तो कभी हमारे साथ कुछ मुद्दों को लेकर समर्थन करती है। और जब किसी बात में हमसे मेल नहीं बैठता है तो क्रिमिनल के साथ हो जाते हैं और राज्य में अराजकता फैलाने में मदद करते हैं। पूर्वे जी भूमि सुधार की बात कह रहे थे इस सम्बन्ध में वे बहुत पुराने सदस्य हैं और मैं नया हूँ। लेकिन वे राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसी बात करते हैं राज्य के 587 प्रखंड में वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है जिससे लोग संतुष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं मुख्य मंत्री का ध्यान एक अत्यन्त ही आवश्यक विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, वह यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकरों के विकास की बात कही गयी है और हमारे राज्य में बुनकरों के लिए जो कॉटन यार्न, सूत की व्यवस्था की जाती है, जो आपूर्ति की जाती है उस पर सैल्स टैक्स की व्यवस्था, जब कि वेस्ट बंगाल में सैल्स टैक्स की व्यवस्था नहीं है, इससे होता यह है कि जो कॉटन यार्न यहाँ आते हैं उस पर 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर और प्रोडक्सन होते-होते 5 प्रतिशत एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बतलाता हूँ कि गया के मानपुर इलाके में 5 हजार पावर और हैंडलूम हैं, सैल्स टैक्स की व्यवस्था के कारण बुनकर परेशान हैं। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 1978 से मार्च 1982 तक सेल्स टैक्स एगजम्प्ट किया गया था। इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि सेल्स टैक्स की जो अभी व्यवस्था है इसको एगजम्प्ट कर दिया जाय ताकि हमारे यहाँ जो 5 हजार पावर एवं हैण्डलूम वर्कस हैं, उन लोगों का व्यापार ठीक से चले और बुनकरों की अवस्था में सुधार हो सके।

श्री राज कुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी दोस्ती से नयी दोस्ती मजबूत होती है। केराला में आर० एस० एस० ने कांग्रेस के साथ गठबन्धन किया है। इसीलिए

अभी नामधारी जी ने जो कांग्रेस के साथ नयी दोस्ती की वफादारी निभायी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

श्री शिव नन्दन पासवान—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री राज कुमार पूर्वे ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए आपका ध्यान और सदन का ध्यान चन्द बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जबसे बाबू चन्द्रशेखर जी बिहार राज्य के मुख्य मन्त्री हुए हैं उनका बहुत लम्बा लम्बा भाषण सुनने का मौका मिला बिहार के लोगों को और उन्होंने बहुत गरज-गरज कर एक नारा दिया कि हम बिहार से भ्रष्टाचार का उन्मूलन का अभियान शुरू कर दिया है। पहले श्रीमती गांधी कहा करती थीं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन उन्होंने हार मान लिया है और हार मान कर कहा कि यह ग्लोबल फेनोमेनन है, विश्व व्यापी है लेकिन अब एक अवतार हुए हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए दिव्य ज्योति अवतरण किए हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अभियान छेड़ दिया है वह है मिस्टर क्लीन ईमेज। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा जिससे बिलकुल स्पष्ट होगा कि कितना भ्रष्टाचार का यह उन्मूलन करना चाहते हैं। इनके कैबिनेट के एक मंत्री श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने इन्हें एक पत्र लिखा और लिखा कि ए० डी० एम०, सप्लाई जमशेदपुर और ए० डी० एम० सप्लाई पश्चिमी चम्पारण इन दोनों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में लिखा कि ये इतने भ्रष्ट हैं कि इन्हें तुरत हटाना चाहिए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन आज तक 6 महीने हो गये उन्हें चिट्ठी लिखे हुए, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

श्री विश्व मोहन शर्मा—ए० डी० एम० सप्लाई, बेतिया से चले गये हैं।

श्री शिव नन्दन पासवान—रामाश्रय बाबू की चिट्ठी की फोटो स्टेट कापी हमारे पास है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन्होंने छोटी-छोटी मछलियों को कुछ ओवरसियर, कुछ सहायक अभियंता को पकड़कर उन्हें सजा दी लेकिन भ्रष्टाचार जिन बड़े लोगों ने की उन्हें कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस शताब्दी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट में हुआ है। आपको मालूम है कि राज्य ट्रांसपोर्ट में घाटा लग रहा है और इसके सम्बन्ध में बहुत चर्चा होती है। कन्डक्टर चोरी कर रहे हैं, खलासी चोरी कर रहे हैं, वहां के इम्पलायी चोरी कर रहे हैं इसके चलते ट्रांसपोर्ट में घाटा हो रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण, राज्य ट्रान्सपोर्ट में घाटे का सबसे बड़ा कारण यह और वह है आर० टी० ए० और एस० टी० ए०, इसमें लोग मिलकर नाजायज परमिट इसू करते हैं प्राईवेट बस के मालिकों को और इसके चलते राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को घाटा होता है। पिछले ढाई तीन सालों में हजारों हजार परमिट नाजायज ढंग से इसू किया गया और इसमें

400 करोड़ रुपये का गोल-माल हुआ है और 400 करोड़ रुपये घूस लिए गये हैं। इस ओर मुख्य मंत्री का ध्यान ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने दिला या और लिखा कि इस पर मुकदमा किया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा किया जाना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ, लेकिन इन्होंने कारवाई नहीं की है। इस आर० टी० ए० और एस० टी० ए० में कुछ वरिष्ट लोग और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए कोई कारवाई नहीं की गयी है। इसमें बड़े बड़े आई० पी० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर शामिल हैं जिन्होंने 400 करोड़ रुपये की लूट की है, इसलिए इन्होंने कोई कारवाई नहीं की।

श्री हेमन्त कुमार झा—मैं माननीय सदस्य को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि टेम्परोरी परमिट एस० टी० ओ० और आर० टी० ओ० के द्वारा नहीं बल्कि डायरेक्ट डिपार्टमेन्ट करता है।

श्री शिव नन्दन पासवान—400 करोड़ रुपये का गोलमाल किया गया है जिनमें बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ प्रभावशाली लोग और बड़े बड़े आई० पी० एस० और आई० ए० एस० शामिल हैं। सारे तथ्य मेरे पास मौजूद है और उसका फोटो स्टेट कापी मौजूद है। इन्होंने कोई कारवाई नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर जिक्र करना चाहता हू। इनके मंत्रि परिषद् के एक सदस्य ने इन्हें चिट्ठी लिखी पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, रांची पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। किस तरह वहाँ के पदाधिकारी ने गोलमाल किया है, भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्ट तरीके से लूट किया है। इनके बाई एलेक्शन के समय साढ़े तीन लाख रुपये ए० प्रभावशाली राजनीतिज्ञ को दिया गया है।

सदस्यगण—किस मंत्री ने लिखा है ?

श्री शिव नन्दन पासवान—श्री बन्दी उरांव ने चिट्ठी लिखी है लेकिन इन्होंने कोई कारवाई नहीं की।

श्री लालू प्रसाद—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न है कि जो रुपया दिया गया वह चुनाव में खर्च हुआ या जिसे मिला उसी ने रख लिया।

उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—माननीय सदस्य सरासर गलत कह रहे हैं। कभी ऐसी बात नहीं हुई है, यह मनगढ़ंत बात है। कुछ लोगों ने मिलकर उनसे चिट्ठी लिखवायी होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ, मिस्टर बकड़ा का ससपेन्शन हुआ है।

श्री शिव नन्दन पासवान—माननीय मंत्री ने कहा कि माननीय राज्य मंत्री से किसी ने चिट्ठी लिखवायी होगी। वे गलत हैं या ये गलत हैं, दोनों में से कोई एक आदमी ही सही होगा इसलिए आज ही मुख्य मंत्री को एक आदमी को डिसमीस कर देना चाहिए। एक राज्य मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी वह गलत हो सकते हैं या मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वे सही हो सकते हैं दोनों बातें तो सही नहीं ही हो सकती है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि दोनों में से एक को डिसमिस किया जाय। अंत में, मैं यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि इसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक और घोटाला हुआ है। एक आई० पी० एस० ऑफिसर के द्वारा फोरजरी की गयी है। जब श्री शंकर दयाल सिंह मंत्री थे, उसी रोज उनका इस डिपार्टमेंट से तबादला हो गया था और एक बड़े आई० पी० एस० पदाधिकारी ने मिनिस्टर के आर्डर को काट दिया और सिर्फ उनका दस्तखत रहने दिया जिससे कि उनका आदेश ही बदल गया, इसमें फोरजरी की गयी है। मैंने मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और इस ऑफिसर के सम्बन्ध में, मैंने प्राईम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पत्र लिखा, प्राईम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर द्वारा कारंवाई की जा रही है, इसका सूचना मुझे दी गई लेकिन मुख्य मंत्री ने कोई कारंवाई नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री बड़े ही निष्पक्ष हैं, निष्पक्षता का दावा करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि हम सड़क बनवाने जा रहे हैं, जो बड़े-बड़े गाँव हैं उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा जायगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वैशाली जिला में मेरा प्रखण्ड है जहां का प्रखण्ड मुख्यालय ही पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

हमारे यहां प्रखण्ड मुख्यालय में भी सड़क का पक्कीकरण नहीं किया गया है और जहां पर कांग्रेसी एम० एल० ए० का क्षेत्र है वहाँ पर पक्की सड़क बना दिया गया है। यह सरासर अन्याय है। इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मांग का समर्थन करता हूँ क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। श्री राज कुमार पूर्वे ने अतिथिशाला और सचेतक के बारे में जो कहा है, उस पर मेरा कहना है कि इस पर तो नगण्य खर्च होता है, नाम मात्र का है।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। ये किस तरह से विरोधी दल के लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं, यह ठीक नहीं है।

(शोरगुल होने लगा)

श्री बालू प्रसाद—मेरा भी प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है। मैं इनके समर्थन में बोलना चाहता हूँ।

(शोरगुल)

श्री रामजी प्रसाद सिंह—ये सब विरोधी वाले लोग सिर्फ जनतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं श्री राजकुमार पूर्वे को कह देना चाहता हूँ कि कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग यहाँ पर सत्ता में नहीं आ सकते हैं, उनकी सत्ता मिलने वाला यहां पर नहीं है। ये सिर्फ मजदूरों को लड़ाते रहते हैं।

(शोरगुल होने लगा)

श्री रमेन्द्र कुमार—मैं इनसे पूछना चाहता हूं……

उपाध्यक्ष—हाँ, आप क्या इनफारमेशन चाहते हैं ?

श्री रमेन्द्र कुमार—जब ये कांग्रेस एम० एल० ए० लोग प्रधान मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो प्रधान मंत्री 'श्रीमती इन्दिरा गांधी इनलोगों से यही कहती हैं कि आपलोग बिहार वाले सब चोर हैं।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—बिल्कुल गलत। आपलोगों के जैसा हमलोग नेताविहीन नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री राजकुमार पूर्वे बराबर ट्रेन से यहां आते हैं और अपना टी० ए० बिल कार से पास करवाते हैं या लेते हैं।

उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हुं कि हमारे क्षेत्र में दो जगह घनडाहा और सोया में बिजली का सब-टेशन बन रहा है लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन सब-स्टेशनों का निर्माण शीघ्र करावें। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। साथ ही मुझे यह कहना है कि हमारे क्षेत्र, बड़हरा कोइलवर में बहुत जगह ट्रांसफोर्मर लगे हुए हैं लेकिन उनमें अधिकांश खराब पड़े हुए हैं और काफी दिनों से खराब है जिससे सिचाई का काम बहुत ठप्प है। इसके बारे में मैंने कई बार कहा है और लिखकर भी दिया है लेकिन उसको अभी तक बदला नहीं गया है। अतः मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे कर उनको शीघ्र बदलवा दें।

अब मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र में गंगा के कटाव से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सोहरा, त्रिभुवानी, पिपरापाती तथा केवटिया में गंगा नदी के बाढ़ से पूर्ण रूप से कटाव हो रहा है और अभी भी जारी है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे कटाव को शीघ्र रोका जायगा। इन क्षेत्रों में कटाव से सबधित सर्वेक्षण भी हो चुका है लेकिन पैसा के अभाव में काम नहीं हो रहा है। अत: मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में कटाव को रोकने के लिए शीघ्र कारंवाई की जाय।

हमारे यहां (आरा में) बाबू कुंअर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक उस दिशा में कारंवाई नहीं हो रही है। अत: इस ओर शीघ्रातिशीघ्र कारंवाई की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सोन कैनाल सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त सिस्टम है और यह एक वरदान स्वरूप है। लेकिन मैं इसके बारे में यही अनुरोध सरकार से करना चाहता हूं कि सहार से कोईलवर तक इसके नहर को बढ़ाया जाय और उसमें पानी देने का प्रबंध कराया जाय। इसका बहुत कुछ निर्माण हो भी चुका है लेकिन उसको कोईलवर तक बढ़ाने की बात है। इसको पूरा किया जाय। इससे काफी सिंचाई किसानों को मिल सकती है।

पुलिस की बहाली में बहुत से लड़कों का नाम वेटिंग लिस्ट में है और उनका सेलेक्सन हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि उनको बहाली कर दी जाय।

सरकार का एनाउन्समेंट था कि हर प्रखंड में एक उच्च बालिका विद्यालय खोला जायगा। हमारे क्षेत्र बड़हरा में एक बालिका उच्च विद्यालय है जिसकी सारी औपचारिकतायें पूरी कर स्वीकृति मिल गयी है। इसका शीघ्रातिशीघ्र टेक ओवर कर लिया जाय।

हमारे क्षेत्र में जितने राजकीय ट्यूबवेल्स हैं उनमें अधिकांश की हालत खराब है और सिंचाई का काम ठप्प है। इसलिए खराब राजकीय ट्यूबवेल्स की मरम्मती शीघ्र करायी जाय।

श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राजकुमार पूर्वे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात यह है कि क्यों इस सरकार को मौका दिया

जाय और डिमांड पास किया जाय जबकि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोग भूख से मरते हैं तो मरने दीजिये। इनका आंकड़ा है कि खरीफ और रबी दोनों फसल मिलकर 24 हजार टन पैदा हुआ था। इसमें खरीफ का लक्ष्य था 79 हजार टन लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि 24 हजार टन भी पैदा नहीं हुआ है। इसके बारे में उनसे कहा गया है कि मौनसून की खराबी से पैदा नहीं हुआ। इसके बारे में जिला स्तर से लेकर प्रान्त स्तर तक बताया गया और मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा लेकिन उन्होंने कहा कि मरने दीजिए तो ऐसी हालत में क्यों इनको पैसा दिया जाय। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री एक जगह लोन बांटने के लिए गये हुए थे और 2,400 लोगों को लोन दिया गया, ऐसा कहा जाता है लेकिन मैं कहता हूं कि 1,200 लोगों को भी नहीं बांटा गया है।

मुख्य मंत्री जी जहां जाते हैं सिर्फ भाषण देते हैं, कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मैंने २० सूत्री का अध्ययन किया है, ये मिटिंग करते हैं, कमिश्नर, कलक्टर को इसमें बुलाया जाता है, सिर्फ कागज पर काम हो रहा है, कोई प्रगति का काम नहीं हुआ है। ये जब चलते हैं तो कमिश्नर, कलक्टर का एक काफिला चलता है, सरकारी पेट्रोल खर्च किया जाता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है।

[***]

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। पिछले दिनों की घटना है। परसों मैं मुजफ्फरपुर में था। वहां पर मुख्य मंत्री जी गए थे। 24 तारीख को जब मुख्य मन्त्री जी वहां पर गए तो वहां पर 24 घंटे बिजली रही लेकिन जब वे लौट गए तो साथ-साथ बिजली भी चली गई। कहने को कहा जाता है कि 600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है लेकिन मुश्किल से दो या तीन मेगावाट बिजली पूरे मुजफ्फरपुर जिला में दिया जा रहा है। बिजली के अभाव में सिंचाई का काम भी नहीं हो रहा है। भले ही हम विधायकों को पटना में बिजली, पानी मिल जाती है लेकिन अन्य जगहों पर बिजली नहीं मिल पाती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में बिजली पूरी नहीं दी जाती है। 48 राजकीय नलकूप वहां पर हैं लेकिन 100 एकड़ भूमि की भी सिंचाई नहीं हो सकी है इधर दो-तीन वर्षों के अन्दर। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बिजली पर इतना रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है, पाईप

टिप्पणी—[***] आसन से अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

बिछाया जाएगा। पाईप आता है लेकिन कहाँ चला जाता है। जहां चुनाव होता है वहां पर पाईप धड़ल्ले से चला जाता है।

मैं देखता हूं कि चाहे बांका चुनाव हो चाहे दलसिंह सराय चुनाव हो तो वहां पर घर में पाईप किस तरह से लगाया गया। मगर हम विरोधी पक्ष के क्षेत्र में पाईप नहीं दिया जाता है। इसी तरह से सड़क की बात है। विरोधी पक्ष के सदस्यों को तीन किलोमीटर रोड़ दिया जाता है तो दूसरी ओर कांग्रेस (आई) के विधायकों के लिए तीस-तीस किलोमीटर रोड दिया जाता है। इस तरह से पक्षपात किया जाता है। इसलिए मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री मो० यासीन—श्री पूर्वे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव लाया है उसका मैं मुखालफत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी पूर्वे जी का बयान मैंने सुना। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में बताया, तो मैं पूर्वे जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में किस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है और सभी लोग चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी ही मिले। तो उनको सोचना चाहिए कि कैसे सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? ऐसे तो सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कई तरह की योजना चालू कर रखी है, जैसे आई० आर० डी० पी० तथा एन० आर० ई० पी० योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैय्या करने की कोशिश की जा रही है हमारी सरकार के जरिए। इसलिए पूर्वे जी को सोचना चाहिए कि सबों को सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? हमारी सरकार ने पब्लिक की भलाई के लिए बहुत सारी योजनायें चला रही हैं और बहुत-सारे काम किए जा रहे हैं। हमारे विरोधी दल के लोगों को सरकार की योजनाओं में सहयोग करना चाहिए। लेकिन वह हमारी सरकार का हर मामले में मुखालफत ही किया करते हैं। हमारी सरकार ने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए विरोधी दलों से भी सहयोग मांगा था मगर इनलोगों ने सहयोग देने के बजाय सरकार के सब कामों का मुखालफत ही किया। फिर भी हमारी सरकार ने सुखे का मुकाबला बड़ी मुस्तैदी के साथ किया। पता नहीं हमारे विरोधी पार्टी के लोग आखिर चाहते क्या हैं?

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सरकार ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुए कुछ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। इस बजट में बिहार मदरसा

बोर्ड को चार लाख पचास हजार रखा गया है और बिल्डिंग के लिए चार लाख रखा गया है। पिछले बजट में मदरसा बोर्ड के लिए कुछ अधिक रकम रखी गई थी मगर इस साल के बजट में इसको घटाकर चार लाख पचास हजार कर दिया गया है। इस तरह से बजट में कटौती की जाएगी तो मदरसा के टीचर्स भूखों मरेंगे। एक ओर हमारी सरकार उर्दू को सेकेंड लैंगवेज बनाने की बात कहती है और दूसरी ओर मदरसा बोर्ड के बजट में कटौती करती है तो इसपर हमारी सरकार को गौर करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं मैंने कई बार अपने क्षेत्र के सड़क के बनाने के संबंध में सदन में चर्चा की है। लोक निर्माण विभाग इसको ले लिया है। इस सड़क का प्लान एसटिमेट बन गया है लेकिन सरकार में यह संचिका घूम रही है, अभीतक सड़क बन नहीं पायी है। अतः इसे अविलम्ब बनाने की कृपा की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिजुलियामायनर टूट गया है और पानी खुलता है तो पूरा इलाका दह जाता है। पानी तो इससे किसान को मिलता ही नहीं है लेकिन एक बार पानी आ जाने के कारण पूरा इलाका दह जाता है। 20 सूत्री के माध्यम से भी हमने उठाया तो कहा जाता है कि टेन्डर हो रहा है। यह टेन्डर दो वर्षों से हो रहा है। इस नहर को अविलम्ब बनाने की व्यवस्था सरकार करावे। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णियां और कटिहार जिले में बंगाल से आकर मुसलमान आ बसे हैं यह गलत नारा विरोधीदल वालों ने लगाया फलस्वरूप 12 हजार मुसलमान जिनका नाम 1980 के वोटर लिस्ट में अंकित था उन्हें हटा दिया गया है और कहा जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं हैं, बंगला देश के नागरिक हैं। इसका पबलिकेसन भी हो गया है। यह बहुत बड़ा जुल्म है कि हिन्दुस्तान के रहने वालों को वोटर लिस्ट से छांट दिया जाय। यह बहुत शर्मनाक बात है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक सदन की कमिटी बनायी जाय जो वहां स्थल पर जाकर जांच करे कि किस तरह उनलोगों के साथ जुल्म हो रहा है।

श्री गणेश प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो सेकेंड सप्लीमेंटरी बजट पेश किया है उसके लिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से दरखास्त करूंगा कि वे इस बजट को रिजेक्ट कर दें। इस बजट को इसलिये रिजेक्ट कर दिया जाय कि यह जो सरकार है वह जनतंत्र की नींव पर खड़ी नहीं है बिल्कुल डंडे के नींव पर खड़ी है। मुख्य मंत्री को जो जब दिल्ली से पटने लाया गया तो पटने के राजभवन में विधायकों का जो

फीजिकल परजेन्स था उसमें इनका बहुमत नहीं था और आज भी इनका बहुमत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुमत नहीं रहते हुए भी ये मुख्य मंत्री के पद पर हैं। ऐसा क्यों हुआ उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कहना चाहता हूं। आज श्रीमती इन्दिरागांधी के डंटे के भय से तमाम लोग बन्धुआ मजदूर की तरह सिर झुकाकर श्री चन्द्रशेखर सिंह के साथ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये विधायक लोग बन्धुआ मजदूर नहीं रहते तो इगनोर करते। आपलोगों ने इगनोर नहीं किया इसलिये मैं मानता हूं कि आप बन्धुआ मजदूर हैं।

श्री रघुनाथ झा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस डिसप्लीन के कायल है उसी तरह से दूसरे के बारे में भी सोचते हैं।

श्री गणेश प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। आज जो सरकार है और उसके जो मंत्री है, मुख्य मंत्री चन्द्रशेखर सिंह को छोड़कर सभी संतरी है मंत्री नहीं है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सरकार अपनी उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है श्री चन्द्रशेखर सिंह, आवाम की खिदमत के लिये मुस्तैद रहें, चन्द्रशेखर सिंह, हम जनता की सेवा के लिये कृतसंकल्प हैं चन्द्रशेखर सिंह, प्रशासन जनता की सेवा में समर्पित रहे, चन्द्रशेखर सिंह, अल्पसंख्यकों को हर कीमत पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी, चन्द्रशेखर सिंह पंचायतें जनतंत्र की बुनियाद है, चन्द्रशेखर सिंह, विकास कार्यों में जनता सहयोगी बने, चन्द्रशेखर सिंह, हमारी नयी कोशिशें चन्द्रशेखर सिंह ये बहुत सारी बातें हैं जिसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। सब पर निगाह हैं चन्द्रशेखर सिंह। इनके कोई कलक्टर भी नहीं है। एन० के० सिंह एक कमिश्नर है। भागलपुर के जिनके पीछे बहुत सी सरकारी गाड़ियां चलती है। ये आई० आर० डी० डी० पी० में गाय, भैंस, बंटवाने में काफी गोलमाल किया है। एक वे हैं सुपर चन्द्रशेखर सिंह जिनका नाम श्रीमती मनोरमा सिंह है।

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल)

श्री विश्वमोहन शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी का नाम लेकर और महिला का खास नाम लेना ठीक नहीं है।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

उपाध्यक्ष—इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिए। उसको निकलवा दिया जाय कार्यवाही से।

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल)

श्री फालगुनी प्रसाद यादव—उपाध्यक्ष महोदय, गलत बात होगी तब न निकलवा दिया जायेगा।

(सदन में हल्ला)

उपाध्यक्ष—इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। आरोप ऐसा हो जिसमें स्टैंडर्ड हो, निम्न प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—गलत होगा तब उपाध्यक्ष महोदय।

(इस अवसर पर सदन में काफी शोरगुल)

श्री गणेश प्रसाद यादव—अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में श्री लालू प्रसाद यादव ने एक काल एटेन्सन किया था रांची के पशुपालन के निदेशक के संबंध में। सारी बातों की जांच हुई और जांच करनेवाले के० सुब्रमण्यम थे। उन्होंने जांच किया और जांच रिपोर्ट दिया। उसमें लिखा था कि श्री लकड़ा को सस्पेन्ड किया जाय। जांच प्रतिवेदन में यह भी लिखा गया है कि इसमें दो मंत्री संलग्न है और यह भ्रष्टाचार का मामला उनसे संबंधित हैं इसलिये कार्रवाई करने का पावर हमको नहीं है। अतः इसकी जांच लोकायुक्त के द्वारा करायी जाय। जो मंत्री उसमें संलग्न हैं माननीय मुख्य मंत्री ने फिर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। उस मंत्री का नाम है श्री एल० पी० शाही उद्योग मंत्री। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि योजना राज्य मंत्री श्री बंदी उरांव ने एक पत्र लिखा है उसमें 7 बिन्दुओं पर उसने लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में मंत्री पर आरोप लगाया है। यदि मंत्री पर लगाये गये आरोप गलत हैं तो राज्य मंत्री बंदी उरांव को तुरत सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। यदि आरोप सही हैं तो मंत्री को हटा दिया जाना चाहिये। बंदी उरांव ने अपने पत्र में सारी बातों की चर्चा की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यह विस्मय की बात है कि इस पत्र का फोटो स्टेट कापी श्री वर्मा के पास कैसे पहुंच गया मुख्य मंत्री के कार्यालय से! माननीय मुख्य मंत्री दो वैसे आदमियों को अपने मंत्रिमंडल में लिया है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जब श्री चन्द्रशेखर सिंह जी को बिहार का चार्ज मिला वैसे मुसलमान को अपने कैबिनेट में लिया जिनपर आरोप है और वे कहते हैं कि अब मुसलमान ठीक है। श्री महावीर पासवान जो पहले मंत्री नहीं थे उस समय राज्य के हरिजनों पर काफी अत्याचार हो रहा था कहते थे लेकिन जब से वे मंत्री हो गये हैं राज्य के अंदर हरिजनों पर से अत्याचार समाप्त हो गया है। जब श्री रामजयपाल सिंह यादव और बुद्धदेव बाबू मंत्री नहीं थे तबतक यादवों पर और पिछड़ों पर अत्याचार हो

रहा था वे कहा करते थे। लेकिन अब यादवों और पिछड़ों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। इस तरह से होता है कि मंत्री बन जाने के बाद बिहार की कुर्सी पर आ जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन आप समझ लीजिये कि बिहार की 7 करोड़ जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपके समय में मसौढ़ी में पिपरा में हत्याकांड हुआ, अखबार में सारी बातें छपी है लेकिन सरकार के तरफ से कुछ नहीं किया गया है। मसौढ़ी में भूमिसेना वहाँ के हरिजनों को हत्या कर रही है। उनकी हत्या कैसे हो रही है उनके पीछे कांग्रेस (आई) के सदस्यों का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं कि नूतन कहानियां में छपा है 2, 4, 5 कहानियां हैं जिसमें सारी बातें कही गयी है। अगर नूतन कहानियां में लिखी बातें गलत हैं तो आप उसके प्रकाशक पर संपादक पर मुकदमा कीजिये। यदि आप में हिम्मत हैं तो उनपर मुकदमा कीजिये। उसमें लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर में माफिया गिरोह में मंत्री जी संलग्न है। यही आप लोकतंत्र के हिमायती है। बिहार के विस्कोमान को जो आपने डिसमीस किया है वह गैर कानूनी ढंग से किया है।

श्री रामाश्रय राय—उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक, 1984 स्वीकृति के लिये इस सदन में पेश है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सदन के माननीय सदस्यों से नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को बिना समय लगायें अनुमति दें। सदन में आया है उसके बहुत उद्देश्य हैं, उद्देश्य है जन-कल्याण, उद्देश्य है गरीबों का कल्याण, एवं उन वर्गों तक सहायता पहुंचना, उन वर्गों को मदद करना और हरिजन हों, गिरिजन हों और पिछड़े हों सभी के विकास में मदद करना। इसीलिये यह विधेयक अविलम्ब स्वीकृत हो। इसीलिये माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिये मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर तथा कुछ आपके क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सदन में विनियोग विधेयक पेश है और इसके द्वारा काफी रुपया दे रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिसका निराकरण अविलम्ब आवश्यक है। रोसड़ा से सुरहाचट्टी रोड को छठी पंचवर्षीय योजना में डा० जगन्नाथ मिश्र ने स्वीकृति दे दी है। हथौड़ी घाट पुल की भी स्वीकृति छठी पंचवर्षीय योजना में हो गयी है। मैं माननीय मंत्री जो अभी सदन में बैठे हुये हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना कागज देखे कोई कह देता है कि यह छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है उसको आप मान लेते हैं, ऐसा न करें बल्कि कागज देख लें। यह

समस्तीपुर की महत्वपूर्ण योजना है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि उस योजना का काम अविलम्ब प्रारम्भ करा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में एक पुल बनाना था जिसे हसनपुर में पुल को तोड़ दिया गया है और उसका लोहा-लकड़ आदि बेंच दिया गया। बरसात में रास्ता बन्द रहता है और कान में पुलिया डालकर विभाग बैठ गया है। अभी लोक निर्माण विभाग के मंत्री यहां नहीं है, अगर इस तरह से काम होगा तो अगले चुनाव में आपको जबाब देना होगा। पुलिया का टेन्डर हो गया है। नरहन-महरानीपुर सड़क तथा सिंघिया घाट में पुल कब से बन रहा है और सदन में आश्वासन हुआ कि जून तक तैयार करा देंगे। राज्य मंत्री कह रहे थे कि डंका की तरह पुल मुंह बाये खड़ा है और आपका पुल निर्माण निगम ठकठक मुंह बाये बैठा है। कहते हैं कि गंभीरता से उस योजना को पूरा करेंगे। आप तुरत जांय वहां, चाहे आपको कुछ भी स्थिति हो लेकिन आप जांय। इससे जो आपने सदन में आश्वासन दिया है उसकी पूर्ति होगी और जो मानन मानने को बात है उसको भी पूर्ति होगी। आप जाइये और देखिये कि क्या स्थिति है क्योंकि एक महीने में बाढ़ आने वाला है और बाढ़ में पुल बनेगा नहीं और अगले साल में जून में न आप रहेंगे और न हम रहेंगे। जनता क्या करेगी देखिये। मैं कुछ और समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। ग्रामीण सड़कें स्वीकृत हुई और सदन के प्रत्येक विधायक के क्षेत्र के लिए 5-5 कि० मी० आर० ई० ओ० की सड़कें स्वीकृत की गई। इन्होंने जो फीगर दिया है उसके मुताबिक अबतक 1 हजार कि० मी० सड़क बनी है जबकि 15 सवा सोलह हजार कि० मी० सड़क बननी चाहिये। चार वर्ष लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में आम चुनाव भी होनेवाला है लेकिन जो आपका 10 हजार कि० मी० का जो फीगर है पूरा नहीं हुआ है, जिस गति से आर० ई० ओ० काम कर रहा है उससे ऐसा नहीं लगता है कि काम पूरा होगा उसके पास पैसे का भी अभाव है। जो कुछ भी पैसा उसके पास जाता है वह पिछले ठीकेदारों को पेमेंट करने में ही चला जाता है। नये को कुछ भी पेमेंट नहीं होपाता है। हमारा जो कमिटमेंट है, आश्वासन है कि प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 कि० मी० बना देंगे वह भी पूरा नहीं होगा इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी स्वीकृत योजनायें हैं उन योजनाओं को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए। जो भी कमी हो फाइनेन्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है उससे लेकर पूरा किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में आपका ध्यान शिक्षा विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं और अपनी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज बिहार के लगभग 20 हजार

इन्टरमीडिएट कालेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी आन्दोलन पर हैं जिसके कारण सारे के सारे कालेज बन्द हैं 500 से अधिक लोग बिहार के कई जेलों में और नजदीक के जेलों में बन्द हैं और इस प्रकार उनके सामने भूखमरी की समस्या है। कॉलेज खोले गये। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि कॉलेज खुलेगा तो कॉलेज की मंजूरी दी जायेगी और उनकी मंजूरी भी हुई। इससे 20-22 हजार आदमी प्रभावित हैं लेकिन एक पैसा भी सुविधा नहीं मिल रही है, न उनकी सेवा शर्त्त निर्धारित हुई हैं और न उनके लिये दरमाहा कौन देगा कहां से देगा यह भी निर्धारित नहीं हुआ है। कितने पैसे की सुविधा होगी, कहां तक पढ़ाई होगी कौन क्या पढ़ायेगा कोई भी चीज निर्धारित नहीं हुई है। सारी चीजें अस्थिरता की स्थिति में है। शिक्षक आन्दोलन की राह पर हैं। माननीय शिक्षा मंत्री सदन में नहीं हैं, और कई मंत्री यहां उपस्थित हैं उनके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही इन शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। उपाध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किये हैं और भी काम होनेवाले हैं लेकिन किसानों के सम्बन्ध में मुख्य समस्या सबसिडी की है। पिछले दो वर्षों से जो सबसिडी दी जाती थी उसमें कुछ कमी हुई है। अर्थाभाव हो सकता है। सबसिडी कम होने से जो एक उफान किसानों के बीच में आया था, किसानों के हृदय में एक आशा बंधी थी कि खेत सूखा नहीं रहेगा और खेत में हरियाली आयेगी वह सब ज्यों का त्यों रह गया। किसानों में यह आशा बंधी थी कि वह अपने खेत को सिंचित कर सकेगा और सबसिडी के माध्यम से निजी नलकूप द्वारा वह अपनी जमीन की सिंचाई कर सकेगा क्योंकि सरकारी नल कूप से सबों को निराशा मिली थी और सब लोगों को असन्तोष था लेकिन आज उसमें भी तरक्की इसलिये नहीं हो रही है कि सबसिडी की रकम ब्लाक तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो बैंक है वह भी सबसिडी नहीं देता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि हरित क्रान्ति आवे, हरित क्रान्ति के लिये आपने जो नारा दिया है उसकी पूर्ति हो सके तो अधिक-से-अधिक सबसिडी अविलम्ब किसानों को उपलब्ध कराई जाए। अभी माननीय मंत्री श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह नहीं हैं, कृषि मंत्री भी नहीं हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहरों से ही कुछेई हवा चलती है और शहर के विकास से ही गांवों के विकास की ओर हवा आगे बढ़ती है। गांवों में विकास के लिए हमने कुछ योजनाएँ बनाई हैं और उसके लिए काम होने वाला है लेकिन आज नगरों की दशा, नगरपालिकाओं की दशा, नगरनिगमों की दशा, अधिसूचित क्षेत्र

समिति की दशा कुछ चिन्तनीय है क्योंकि उनके पास धनाभाव है। उनके कर्मचारियों को दरमाहा देने के लिए पैसा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों की सड़कों के विकास के लिए शहरों में जो कुछ भी योजनाएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए अविलम्ब पैसा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में रोसड़ा रेफरल अस्पताल था लेकिन जब अनुमंडल हो गया तो उसे सबडिवीजनल अस्पताल में बदल दिया गया लेकिन उसके लिए एक भी सुविधा नहीं दी गई। लगभग तीन लाख रुपये के व्यय से वहां एक एक्सरे मशीन बैठायी गई लेकिन टेकिनशियन के पोस्ट के क्रियेशन के अभाव में तीन वर्षों से वह बेकार पड़ी हुई है। इसके लिए मैंने और सिविल सर्जन ने काफी कोशिश की लेकिन वह मशीन एक टेकिनशियन के अभाव में पड़ी हुई है जिससे सारा काम अस्पताल का पड़ा हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक बात और कहनी है कि रोसड़ा के लिए एक हयपीरो रेफरल अस्पताल खोलने की ओर सरकार अविलम्ब ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, उदयनाचार्य जी बिहार ही नहीं सम्पूर्ण भारत के कितने बड़े विद्वान फिलॉसाफर थे। उनकी जन्मभूमि रोसड़ा के करियन ग्राम में है और संस्कृत के इतने महान् पुरुष की स्मृति में करियन ग्राम में पर्यटन विभाग द्वारा आज तक कोई स्मारक नहीं बनाया गया, आज वहाँ कोई स्मारक नहीं होने की वजह से ग्राम में कोई यात्री पहुंचे तो वह यह नहीं देख सकता है कि इतने बड़े महापुरुष के लिए इस करियन ग्राम में पर्यटन विभाग की ओर से कुछ किया गया है। मैं पर्यटन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और उन महापुरुष का सम्मान करते हुए उनका स्मारक वहाँ बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और सहर्ष इस विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का, आदिवासियों की योजनाओं में मदद करने का दम्भ भरा है। बात बात में आदिवासियों की मदद की चर्चा करते हैं। मैं कुछ इन्सटांस देकर, कुछ उदाहरण देकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हजारीबाग में रामगढ़ क्षेत्र में एक बड़े पूंजीपति हैं। उस आदिवासी को 5 सौ रुपया देकर 4 एकड़ 10 डिसमिल जमीन अपने हक में लिखवा लिया है। इसके बारे में एल० आर० डी० सी० ने लिख दिया कि आदिवासी की जमीन है, वहीं के एस० पी० ने लिखा कि यह आदिवासी की जमीन है लेकिन इसके बाद भी डिप्टी कमिश्नर ने उस पूंजीपति की मदद करने के लिए उस जमीन पर

बन्दूकधारी पुलिस फौज को भेज दिया है। एम० पी० की बात की उपेक्षा करके, एल० आर० डी० सी० की बात की उपेक्षा करके उस पूंजीपति को जमीन दिलाने की साजिश की गयी है। उस जमीन पर आदिवासी को कब्जा दिलायी जाय। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। दूसरा मुद्दा मैं यह उठाना चाहती हूं कि जैसे हरिजन और आदिवासियों को सुविधा दी गयी हैं उसको नन-आदिवासी लोग हड़पना चाहते हैं और सरकार भी उसमें साझेदार बनती है। कार्मिक विभाग से एक सर्कुलर 1040/99 और 1040/106 निकला है। उस सर्कुलर में क्लियरकट लिखा हुआ है कि अगर आदिवासी मां है, पिता गैर-आदिवासी है तो उसका बच्चा आदिवासी माना जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहती हूं। आदिवासियों की सुविधा को हड़पने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा सर्कुलर निकाला गया है। इस सर्कुलर को सरकार शीघ्र वापस ले ले क्योंकि हमारा देश मातृप्रधान देश नहीं है। यदि सबके लिए यह मातृप्रधान मान लिया जाय तब तो कोई बात नहीं है लेकिन आदिवासियों की सुविधा को हड़पने के लिए ऐसा किया गया है और इस तरह का सर्कुलर निकाला गया है अतः इस सर्कुलर को सरकार को वापस लेना चाहिए। इसका मैं एक इन्सटांस यह देना चाहती हूं कि आज सेंट कालम्बस कॉलेज के बहुत से लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। आज स्कूलों में, कॉलेजों में आदिवासियों के नाम पर दूसरे लड़के छात्रवृत्ति उठा रहे हैं और आदिवासियों के हक को हथिया रहे हैं। इसलिए मां आदिवासी और बाप गैर-आदिवासी वाला सर्कुलर सरकार को वापस लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तीसरा मामला मैं यह उठाना चाहता हूं कि एक रैजवती देवी वहां से गायब हो गयी। थाना में सास श्वसुर ने खबर की। पुलिस ने एक डेड बॉडी को लाकर उसके पति को पकड़ कर मार मार कर कहा कि कहो कि यह तुम्हारी ही पत्नी है। पति बोलता रहा कि नहीं, मेरी पत्नी गोरी है, यह नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी की लाश बताकर, गवाहों को इकट्ठा कर उसके लिए पूरे फांसी का सामान दर्ज कर दिया है। जिस दिन जमानत का मामला डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में गया उस दिन रजवन्ती देवी जिन्दा वापस आ गयी। लेकिन उस दारोगा के खिलाफ सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। अगर रैजवती देवी वापस नहीं आती तो उसके आदमी को और सास को फांसी हो जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा मामला श्रम विभाग के बारे में है। श्रम विभाग के तरफ से कहा जाता है कि श्रमिकों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूनतम मजदूरी

1 सितम्बर, 1983 से 80 पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन इसके लिए आदेश निर्गत नहीं हुआ। कोर्ट में केस गया, स्टे हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोर्ट केस को वापस करने की दिशा में कारंवाई नहीं की गयी ताकि मजदूरों को राहत दिलाया जा सके।

सरकार के सिंचाई विभाग में बांध निर्माण से सम्बन्धित जो कर्मचारी नियोजित हैं उनके महंगाई भत्ता के लिए 1 जुलाई, 1983 को ही आयोग बैठाना था। सरकार का आदेश था, लेकिन आज तक सिंचाई विभाग ने बांध निर्माण के कार्यकर्ताओं के लिए आयोग नहीं बैठाया जिसके चलते उनको वेतन-भत्ता आदि से वंचित रहना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोहतास गयी थी। आज ही वापस आयी हूं। वहाँ सरकार की तरफ से मोची को जूता दूकान खोलने के लिए गुमतियाँ दी गयीं थीं। चर्म-उद्योग के विकास के लिए सरकार ने उन्हें ऋण दिया। 30-40 की संख्या में मोची गुमती में जूता की दूकान खोलकर बैठे थे। वहाँ के अनुमण्डलाधिकारी ने वहाँ जाकर गुमतियों को उखाड़ दिया। गुमतियों को तोड़ दिया और फेंक दिया। इस तरह सरकार एक तरफ रोजगार के लिए गुमती दिया, पैसा भी दिया और दूसरी ओर सरकार के अधिकारी जाकर गुमती को उजाड़ देते हैं। यह कौन-सी नीति है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग के बारे में कहना चाहती हूं कि एक जोती उरांव हैं और उनके अलावे कई लोग हैं जिनको सरकार ने हजारीबाग में कुछ अनुदान दिया। उस अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए वहां के बी० डी० ओ० ने उनलोगों से 20 प्रतिशत घूस की मांग की और कहा कि घूस देने पर ही पैसा मिलेगा। उनकी मंशा भी पूरी कर दो गयी। फिर भी लोगों को पैसा नहीं मिला है। किसी का एक हजार, किसी का 1500, किसी का 4 हजार बाकी है। सारे आदिवासी लोगों को कठिनाई हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला है मशीनीकरण का। सरकार कहती है कि नियोजन बढ़ाना चाहते हैं और स्व-नियोजन के नाम पर बेरोजगारों को 25,000 की राशि बांट रही है। लाल-किले पर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह एलान किया था। लेकिन कोयला खान में दो लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरी की बात कौन करे ? बड़ी-बड़ी मशीनें लायीं जा रही है इसका नतीजा होगा कि एक-एक मशीन 350-350 आदमी का काम करता है। इस तरह लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसमें बिहार सरकार को केन्द्र सरकार से बात कर हस्तक्षेप करना

चाहिए। उनकी जमीन ले ली जाती है और मशीन देकर उनसे काम छीन लिया जाता है जिसके चलते उनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे मांडर क्षेत्र में 47 की० मी० सड़क मंजूर हुई है, लेकिन एक भी सड़क पूरी नहीं हुई है। मंत्री महोदय वहां गये थे और उन्होंने वचन भी दिया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा रहा है। चुरचू एक ऐसा ब्लोक है जो सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इसे पक्की सड़क से जोड़ा जाये। मैं मांग करती हूं कि कोनार नदी पर पुल बनाया जाये। इसी तरह मरगन नदी पर पुल बनाया जाये। इसके लिए 3 वर्षों से टेन्डर होता आ रहा है, लेकिन मार्च आने पर पैसा लैप्स हो जाता है। इस वर्ष फिर टेन्डर हुआ था। लेकिन पुल नहीं बनाया गया, फिर पैसा लैप्स हो जायेगा।

उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जाइए। आप का समय हो गया।

श्रीमती रमणिका गुप्ता—मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि 13000 लोगों की जमीन कोयला खान में चली गयी। वैसे परिवार बेघर-बार के हो गये हैं, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि उन लोगों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है उसको लागू कराये। मेरा सरकार पर मुकदमा भी चल रहा है। उनके लिए जबतक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तबतक सी० सी० एल० कम्पनी को एक इंच जमीन नहीं दी जाये।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि मांडू में विस्थापित लोगों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाये।

श्री नील मोहन सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो मांग रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं मा० विरोधी दल के सदस्यों से अनुनय, विनय और प्रार्थना करता हूं कि कम-से-कम वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें और इस तरह की मांग का समर्थन नहीं करें। क्योंकि वे भी मान चुके हैं कि राज्य में अनुत्पादक व्यय में कटौती कर उत्पादक व्यय में राशि का आवंटन किया गया है जिसके पीछे मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि बिहार में प्रगति हो, रचनात्मक कार्य हो। बिहार के प्रशासन में जनता में एक नयी संस्कृति का अभ्युदय हुआ है जिसे विकास और कार्य की संस्कृति कहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने 20-सूत्री कार्यक्रम के जरिए आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए स्वप्न देख रहीं हैं। उसे कटुता से लागू करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है और यह प्रयास किया जा रहा है, इसलिए

इस मांग का समर्थन किया जाये। हमारे पूर्वजी सदन में नहीं हैं। उनको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री, श्री चन्द्रशेखर सिंह का इमेज राज्य के बाहर और राज्य के अन्दर अच्छा इसलिए माना जाता है कि वे पुअर पिपुल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव जी भाषण तो नहीं कर रहे थे, लेकिन सदन में जोर-जोर से बोलते हुए कह रहे थे कि मनोरमा जी क्षेत्र में घूम-घूमकर मीटिंग कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मनोरमा जी और श्री चन्द्रशेखर सिंह के दल में जाति-पात और साम्प्रदायिकता की दिवाल नहीं है। यह दिवाल टूट रही है।

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव—सरकारी अफसरों का काफिला चल रहा था, इसलिए मैंने कहा।

श्री नीलमोहन सिंह—माननीय सदस्य इतना एजिटेटेड हैं कि क्या कहा जाये? उनसे अनुरोध है कि जाति-पात छोड़कर दूसरे काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हू कि हमारे यहां अमरपुर रोड है जिसका उद्घाटन हो गया। लेकिन टेकिनकल सेंक्शन के अभाव में काम शुरू नहीं हुआ है। बीच में कुछ काम आरम्भ हुआ था, लेकिन टेकनिकल-हिच लग गया है जिसके लिए टेकनिकल-सेंक्शन के लिए भेजा गया है। इसलिए अनुरोध है कि इसको किया जाये।

हमारे क्षेत्र में पी० एच० ई० डी० का वाटर सप्लाई की योजना है। इसके लिए कारंवाई की जायेक्योंकि गर्मी में पेयजल की घोर संकट हो जाता है। इसलिए इसे शीघ्र कारंवाई करे ताकि जनता को पेयजल मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठ जाना चाहता हू।

श्री रमेन्द्र कुमार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों को कुछ राय दे देना चाहता हूं। पहली राय यह है कि हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में राय दें। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने कोयला-खान की मिलें हैं हालांकि राष्ट्रीयकरण हो गया है लेकिन फिर भी बहुत से खदान अवैध ढंग से चल रहे हैं। बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार से बात करके सबको चालू करावे क्योंकि बहुत सी मिलें बन्द हैं इससे बिहार में जो कोयला संकट है वह दूर हो जायेगा दूसरा लाभ यह होगा कि इससे करीब दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तीसरा बिहार सरकार को रायल्टी मिलेगा साथ ही बिजली की कमी भी दूर हो जायेगी इसलिये बिहार की जितनी कोयला खदान मिल बन्द है सरकार उसे चालू कराये। कोयला पर आधारित उद्योग जैसे फर्टिलाइजर, वगैरह का कारखाना शुरू करे। इसके अलावा

यहां माइका उद्योग की हालत भी बहुत खराब है। बिहारे सरकार को इसमें सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिये, इसके माइनिंग में सहयोग करें। माइका उद्योग में बहुत ज्यादा संख्या में गैरकानूनीय माइका माइनिंग हो रहा है इसलिये बिहार सरकार को चाहिये कि जो गैरकानूनीय ढंग से माइका माइनिंग हो रहा है उसको बन्द करायें, इसमें तीव्र गति लायें और माइका उद्योग को टेकनिकल सहायता करे साथ ही जो भी संभव हो दूसरे तरह का सक्रिय सहयोग करे। इसके साथ साथ में कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार का कहना है कि इसके आय का जरिया क्या होगा तो मैं बता देता हूं कि छोटानागपुर में बहुत से उद्योग चल रहे हैं और चल सकते हैं जैसे कोयला का, पत्थर का ईंट भट्ठा जिससे बिहार सरकार को रायल्टी मिलती ही नहीं है और यदि मिलती है तो बहुत कम। इस तरह के उद्योग छोटानागपुर में बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत से खदानों का निरीक्षण किया है जिससे बिहार सरकार को रायल्टी नहीं मिलती है और जो मजदूर वहां काम करते हैं उन मजदूरों को भी खान मालिक पांच रुपया महिलाओं को और छः रुपया पुरुषों को मजदूरी देती है। यह केन्द्रीय सरकार का मामला है। 12 घंटा काम कराया जाय और इतनी कम मजदूरी मिले यह कभी भी उचित नहीं है। इसीसे मजदूर यहां से भागकर कलकत्ता और पंजाब चले जा रहे हैं। यहाँ इससे ज्यादा मजदूरी मांगने पर मजदूरों को पिटाई की जाती है बलात्कार किया जाता है और काम से हटा दिया जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन सब गैर कानूनी ढंग से चलनेवाले खादानों को सरकार अपने जिम्मे ले ले इससे बिहार सरकार को रायल्टी मिलेगा, मजदूरों को उचित मजदूरी मिलेगी।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर में जो सिंचाई की योजना है या दूसरी योजना है या वन में जो काम करते हैं चाहे वह एन० आर० ई० पी० के हों या कहीं के भी हों एक जगह भी बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से बिहार सरकार के प्रत्येक पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता के पास पत्र लिखा है या जाकर कहा है लेकिन कहीं भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। 128 सीएफटी मिट्टी काटने पर 6 रुपया दिया जाता है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने पर इन असंगठित मजदूरों को जो शोषण हो रहा है कोई कारंवाई नहीं हो रहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन भी चल रही योजना में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है।

आपके अधिकारियों को क्या हो गया ? आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, जो ठीकेदार बिल बनाते हैं, उस बिल में न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से बिल बनाते हैं, जो इस्टीमेट

बनाये जाते हैं, वे न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं, लेकिन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी को भुगतान नहीं होता है, यह सिर्फ कानून का उलंघन ही नहीं हो रहा है, बल्कि सरकारी खजाना की भी लूट है, और इस लूट में आपके अधिकारी और ठीकेदार दोनों सम्मिलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बड़कागांव-अम्माजोत 15 कि० मी० की एक सड़क है, जो काफी महत्वपूर्ण है, उस सड़क के अलावा दूसरी कोई सड़क नहीं है, इस सड़क पर प्रखण्ड की ज्यादा आबादी बसी हुई है. बरसात के दिनों में लोगों को काफो जाने-आने में कठिनाई है, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी जो योजना है प्रखण्ड से प्रखण्ड सड़कों से जोड़ने की, उसी के तहत आप बड़कागांव-अम्माजोत सड़क का अविलम्ब निर्माण करायें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके, यदि वह पथ पक्का हो जायेगा तो उस इलाके के लोगों को, वह इलाका एक कृषि प्रधान इलाका है, कृषि पर आधारित पदार्थों का बाजार मिल जायेगा, इससे लोगों की दयन स्थिति में सुधार आ जायेगा।

मैं कांग्रेसी मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं, सभी कांग्रेसी एक ही बात बोलते हैं, इनका कहना है कि सभी कांग्रेसी गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज वह कांग्रेस है नहीं जो आजादी के पहले थी, आज कांग्रेस का अस्तित्व वह नहीं है जो आजादी के पहले था। आज तो कांग्रेस में ऐसे-ऐसे लोग आ गये हैं, जिनकी पैदाईश आजादी के बाद हुई है, आज कांग्रेस के अन्दर असामाजिक तत्वों का बोल-बाला है, आज कांग्रेस वह है नहीं जो आजादी के पहले थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक मिनट में समाप्त ही करने वाला हूं। बिहार के विख्यात इतिहासकार डॉ० विजय चन्द्र चौधरी को प्रोन्नति निदेशक के पद पर इसलिये नहीं किया गया चूंकि उन्होंने वर्ष 1977 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि हिन्दुस्तान के मुसलमान देशी है, विदेशी नहीं, इसी आधार पर उनको सजा दी गयी और उनको निदेश के पद पर प्रोमोशन नहीं दिया जा रहा है। यह पद अभी भी खाली है, लेकिन एक दूसरे आदमी को अस्थाई रूप से कार्य-भार दिया गया है, यदि कांग्रेस अपने को धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक कहती है तो श्री चौधरी का प्रोमोशन अविलम्ब करे। नहीं तो यह कांग्रेस जो पहले वाली थी, वह नहीं है, इस नकली कांग्रेस से लोग सावधान रहें।

श्री यमुना प्रसाद राम—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा ......

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र पासवान एवं माननीय सदस्य श्री भोला सिंह के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गये।)

[सदन में शोर-गुल]

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। इस तरह की अशोभनीय बातें न करें, आप लोग अपनी-अपनी जगह पर चले जायं।

[सदन में शोर-गुल]

शांति, शांति। इस तरह से उत्तेजना में आकर ऐसा दृश्य उपस्थित न करें जो सदन की गरीमा के बिल्कुल प्रतिकूल हो। दोनों सदस्य, माननीय श्री भोला बाबू और श्री रामचन्द्र पासवान सदन के पुराने सदस्य हैं। इस तरह से वे अपने को आपस में न उलझें। माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें और सदन की कारंवाई को चलने दें।

श्री यमुना प्रसाद राम—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो विनियोग संख्या-2 विधेयक 1984 सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी योजनाएं बजट के माध्यम से सदन में प्रस्तुत की गयी है मैं समझता हूं कि वह बिहार के चौमुखी विकास की ओर ले जानेवाला है। अभी कुछ बातें हो रही थीं, पता नहीं हमारे जो विरोधी दल के सदस्य हैं खास करके हमारे भाई हैं जो उलझे हुए थे, बराबर सदन की गरिमा को नष्ट करने धूमिल करने और सदन के वातावरण को कैसे अशांत किया जाय शायद उनको दिलचस्पी इसमें रहती है। चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, दोनों पक्ष के लोग जनता द्वारा निर्वाचित होकर सदन में आते हैं और सदन की गरिमा बरकरार रखने का जितना दायित्व हमलोगों पर है उतना ही हमारे मित्रों पर भी है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जो बात प्रस्तुत करें वह उचित माध्यम से सदन की गरिमा को रखते हुए रखें और सदन में शोरशराबा न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने जिला की ओर ले जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय पूर्णियां जिला एक बहुत बड़ा जिला है जिसे कमिश्नरी का दर्जा मिलना चाहिये था लेकिन आजतक नहीं मिला और वह उपेक्षित है। पूर्णियां जिला में 27 प्रखंड है, जिस इलाके में 4 या 5 प्रखंड थे वे जिला बना दिये गये लेकिन पूर्णियां जिला की जनता ने कौन-सा जुल्म किया है जो आजतक अररिया और किशनगंज को जिला बनाने की बात वर्षों से लंबित है और इसपर निर्णय नहीं लिया गया जिसके चलते इस इलाके के लोगों में आक्रोश है और जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि हर इलाके को सुसज्जित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मजबूत हो और इसी आधार पर जिला बनाया गया ताकि

क्राईम पर कन्ट्रोल हो सके, समुचित विकास हो सके। इसलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्णियां को कमिश्नरी और अररिया तथा किशनगंज को जिला का दर्जा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, गत सत्र में यह तय किया गया था कि हरिजन के कल्याण के लिये जो कल्याण विभाग है उसमें तीन प्रखंड मिलाकर एक वेलफेयर इन्सपेक्टर को रखा गया है जिससे काम नहीं होता है। हरिजन छात्र को, आदिवासी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है हालांकि हमारी सरकार की यह मंशा रहती है और सरकार राशि आवंटित करती है। चूंकि कर्मचारी अनुपात नहीं है, दूसरे विभागों में दूसरे-दूसरे कामों में हरएक प्रखंड में हरएक काम के लिये एक-एक कर्मचारी और पदाधिकारी होते हैं लेकिन कल्याण विभाग में तीन ब्लाक मिलाकर एक वेलफेयर इन्सपेक्टर रखा गया है। इससे सरकार की जो मंशा है उसका समय पर निष्पादन नहीं हो पाता है। इसलिये हरएक प्रखंड में एक-एक वेलफेयर इन्सपेक्टर रखा जाय।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। पूर्णियां के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अभी हाल ही में साढ़े तीन सौ कर्मचारी, ड्रेसर एवं ए० एन० एम० का स्थानान्तरण किया गया है, स्वास्थ्य विभाग का आदेश हुआ कि स्थानान्तरण को स्थगित किया जाय लेकिन इसके बावजूद भी वहां सिविल सर्जन द्वारा इस आदेश की अवहेलना की गयी और उनके स्थानान्तरण को बरकरार रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली की बात करता हूं। माननीय मंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हरिजन गांव में विद्युतिकरण की बात की गयी है। आंकड़े दिये गये हैं कि इतने हरिजन गांव का विद्युतिकरण किया गया है। मैं चैलेन्ज करता हूं और मुख्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं उसकी जांच-पड़ताल करायी जाय कि कितने गांव का विद्युतिकरण हुआ है। बिहार की बात तो छोड़ दीजिये, मैं बैंक हार्डिंज रोड में रहता हूं ठीक कारपोरेशन के कार्यालय के पीछे, आज वर्षों से इस रोड में स्ट्रीट लाईट नहीं है जिसके चलते छीना-छोरी होती है, छुरेबाजी में कितने लोग मारे गये, अभी हाल ही में डकैती हुई है, कई लोगों को और रिक्शा वालों को लूट लिया गया लेकिन आजतक बैंक हार्डिंज रोड में स्ट्रीट लाईट नहीं लगायी गयी है। इधर मच्छड़ का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, शून्य-काल में भी इस बात को उठाया गया है। पहले दवा का छिड़काव होता था लेकिन इधर महीनों से मच्छड़ की दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

श्री शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव—उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज सम्पूर्ण देश में सारे संसदीय संस्थाओं की गरिमा को समाप्त करने के लिये एक षड्यंत्र है इसमें सब कुछ औपचारिकता है, बजट प्रस्तुत करना, विनियोग संख्या-1 या 2 रखना या इस पर बहस कराना। फिर भी मैं औपचारिकता की कड़ी में आपके सम्मुख दो-तीन तत्व रखना चाहूंगा। पहली बात मार्च बजट यह प्रावधान अंग्रेजी राज्य की देन है जो आज भी ज्यों-के-त्यों चली आ रही है। सातवें वित्त आयोग के सामने हमलोगों ने इस बात का रखा था और आयोग ने बड़ा गंभीरता से इस पर विचार किया था। भारतवर्ष को प्राकृति, कृषि और उद्योग-धंधे सब को ध्यान में रख कर बजट के प्रारंभ होने के समय को बदलना चाहिये और यहां जो भारत का आर्थिक वित्तीय वर्ष दिपावली से प्रारंभ होता है उसके अन्तर्गत कृषि और उद्योग का विकास हो सकता है। यह करने की आवश्यकता है। अनुपूरक की मांग आपको बार-बार रखनी पड़ती है विधान-सभा में। विधान-सभा से बजट पारित कराना इसीलिये शायद निरंतर विधान-सभा की बैठकों की संख्या कम होने के बावजूद बजट के लिये आपको विधान-सभा को बुलाना पड़ता है और विधान-सभा से बजट को पारित कराना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार में वित्तीय अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार हमलोगों ने भवन निर्माण विभाग को। करोड़ 90 लाख रुपये आवंटित किये लेकिन भवन निर्माण विभाग को केवल 1 करोड़ 85 लाख रुपया विमुक्त किया गया। परिणाम क्या हुआ ? 1982 के 31 जनवरी के बाद भवन निर्माण विभाग में किसी ठीकेदार को एक पैसे का पेमेन्ट नहीं हुआ। विकास कार्यों का आप जितना ढिंढोरा पीटें लेकिन बिहार का प्रत्येक नागरिक यह जानता है कि 31 जनवरी 1982 के बाद बिहार में कोई ठोस निर्माण कार्य कहीं नहीं हुआ जिसे हम नया कार्य कह सकें। और सैकड़ों ठीकेदारों ने जो सड़क या भवन का निर्माण कार्य किया है, वे वर्षों से अपने विपत्र के भुगतान के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। क्योंकि आप वित्तीय अंकुश को लगाकर बिहार को पीछे खींचते जा रहे हैं। यहां पर विनियोग और अनुदान की मांग करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनका स्वास्थ्य विभाग अस्वस्थ है। मेडिकल कॉलेज में जहां 700 सीट था उसको घटाकर ये 500 कर दिए हैं। यह जाहिर करता है कि पहले की अपेक्षा अब यहां पर कम डाक्टर पैदा होंगे। ये भवन निर्माण कराने में पीछे जा रहे हैं, डाक्टरों की संख्या घटाते जा रहे हैं। फिर भी आपको करोड़ों रुपए किस बात के लिए चाहिए इसका मतलब है कि आपको बिहार के विकास के

लिए रुपया नहीं चहिए बल्कि कुछ विशेष व्यक्तियों के विकास के लिए रुपया चाहिए। सभी विरोधी दल के नेता आपके इस बात को जानते हैं। इतना ही नहीं 20 सूत्री प्रोग्राम के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनी है, उसमें हमारे विरोधी दल के विधायकों को नहीं रखा गया है। इस तरह की राष्ट्रीय समिति में जनता के प्रतिनिधि को आप अलग रखते हैं। यह काम आपका जनतंत्र के पाठ में छूरा भोकने के समान है। उपाध्यक्ष महोदय, चीनी और सीमेंट के आवंटन के लिए जो समिति बनी हुई है, उसके लिए इनका आदेश जाता है कि विरोधी दल के नेता इसमें नहीं रखे जायं। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि विरोधी दल के विधायक अक्षम हैं? सड़क बनाने में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, यह भी सबों को पता है।

जो राशि आवंटित होती है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उसका खर्च सही ढंग से हो। क्या ये किसी के श्रम का शोषण नहीं कर रहे हैं? श्री रामाश्रय राय, जो कांग्रेस (आई०) के विधायक हो हैं, उन्होंने कहा है कि आज शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जेल में पड़े हुए हैं। सत्तारूढ़ दल के लोग अनेक संस्थाओं में पड़े हुए हैं और वित्तीय संकट के नाम पर गरीब कर्मचारियों का वेतन रोका जाता है, जो उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल पटना जिला में ही 400 प्रशिक्षित शिक्षिका 8 वर्षों से योंही पड़ी हुई हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। आपको यह भी पता होगा कि पुलिस विभाग में अनुसचिवीय कर्मचारी सभी-के-सभी हड़ताल पर हैं। पुलिस कमीशन ने जो उनके लिए सिफारिश वर्दी के लिए किया है, उसकी सुविधा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्य मंत्री वित्तीय होवा खड़ा करने में बहुत ही दक्ष हैं। वित्तीय होवा खड़ा करके ये लोगों को डराना चाहते हैं ताकि किसी चीज की वह मांग नहीं करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ मिश्र बिलकुल दूध के धोये हुए हैं लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री ने जो काम किया है, उसका मैं कुछ उदाहरण सदन में देना चाहता हूं।

बिहार राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का स्थान दिया गया है लेकिन स्थिति क्या है इसको देखा जाय। बिहार सरकार ने उर्दू के विकास के लिये 66 लाख रुपया का अनुदान दिया है और हिन्दी के विकास के लिए 33 लाख रुपया दिया है और कहा गया है कि हिन्दी और उर्दू दोनों ही राजभाषा हैं और दोनों का विकास करना है। आप हिन्दी का विनाश चाहते हैं। हिन्दी के साहित्यकारों के साथ जिस प्रकार की

प्रतिष्ठा का व्यवहार हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ है। स्वर्गीय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आदि विद्वानों की आत्मा किस तरह कराह रही होगी, यह आप सोच सकते हैं। जो भी हिन्दी की प्रसिद्धी हुई उसको लीप-पोतकर बराबर कर दिया गया है। उनका कोई सत्कार नहीं, कोई सम्मान नहीं, और कहीं कोई पूछ नहीं है। मैंने शिक्षा जगत की एक तस्वीर आपके सामने रखी है। कल 27 मार्च, 1984 को पटना विश्वविद्यालय के सारे शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं चूंकि उनकी वह मांगे नहीं मानी गयीं जिसको पिछले मुख्य मंत्री ने स्वीकार की थी। मध्य विद्यालय के शिक्षकों से ले कर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह सचमुच अभूतपूर्व है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय, उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात सरकार द्वारा कही गयी थी लेकिन अभी तक नहीं हो सका। आज अल्पसंख्यक भी समझ गये हैं कि उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा जो की गयी थी वह आज कितनी खोखली घोषणा थी।

उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जांय।

श्री रघुनन्दन प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मांग पेश की गयी है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री राजकुमार पूर्वे ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिहार के मुख्य मंत्री बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एग्रीकलचरल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन को ये बढ़ाना चाहते हैं। जैसाकि सभी माननीय सदस्य ने देखा होगा कि 1984-85 में एग्रीकलचरल प्रोडक्शन को 10 परसेन्ट बढ़ाने का अनुमान है, ठीक उसी प्रकार इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन 9 परसेन्ट का अनुमान रखा है। हमारे मुख्य मंत्री बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत सभी पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों को, आदिवासी तथा हरिजनों को, तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आप को जानना चाहिए कि हमारे राज्य में विकास की जो योजना चलायी जा रही है, उस योजना को पहले से 25 परसेन्ट मुख्य मंत्री बढ़ाना चाहते हैं। सिंचाई की क्षमता को भी उसी प्रकार बढ़ाना चाहते हैं। इस पर वे 151.57 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यह वृहद एवं मध्य सिंचाई पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार लघु सिंचाई पर 207-04 करोड़ खर्च करने की योजना है।

आई० आर० डी० पी० में 3,82,200 परिवारों को लाभान्वित करना हमारी सरकार चाहती है। 4,059 समस्याग्रस्त गांवों में पेय-जल की व्यवस्था करने का प्रोग्राम है। गृह विहीनों को घर दिलाने को व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है तथा गन्दी बस्तियों को सुधार कर के 40 हजार लोगों को लाभान्वित करने जा रही है। इन सभी कामों के लिए पैसे की आवश्यकता है, यदि आप एक पैसा भी नहीं दीजिएगा तो ये सारी विकास की योजनाएं कैसे चलायी जा सकती हैं। इसलिये मैं विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब देश और प्रदेश की तरक्की आप देखना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पैसा देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं हजारीबाग के बारे में कहना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हजारीबाग एक ऐसी जगह है जहां रेलवे लिंक नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है और न कोई विश्वविद्यालय ही वहां है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। अभी शिक्षा मंत्री महोदय नहीं हैं, फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं। हजारीबाग में मार्खन कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल, श्री शिव दयाल सिंह हैं। वे रिक्युजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, 47 प्रतिशत मार्क्स उनका है, फिर भी वे घूस देकर वहां के प्रिंसिपल हो गये। इसके लिये न तो कोई एडवरटीइजमेन्ट हुआ और न अखबार में निकला फिर भी उन्होंने कॉलेज सर्विस कमीशन को 25 हजार रुपया घूस देकर अपनी बहाली वहां पर करा ली। रांची युनिवर्सिटी और कॉलेज सर्विस कमीशन को घूस देकर अपना कंफर्मेशन भी करा लिया है। प्रिंसीपल के सर्विस का कंफर्मेशन करने के लिये रूल रेगुलेशन है। कॉलेज सेवा आयोग को उसके आधार पर एडवर्टीइजमेन्ट करना चाहिए था, इन्टरभियू लेना चाहिए था लेकिन यह सब कुछ नहीं किया गया। कॉलेज सेवा आयोग के अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने 25 हजार रुपया घूस लेकर, हजारीबाग के प्रिंस होटल में बैठकर उनके सर्विस को कन्फर्म कर दिया। वे सेंट कोलोम्बस कॉलेज के हिन्दी के टीचर हैं, वे वहां पर लिएन पर थे। उनका लिएन समाप्त हो गया था। उन्होंने लिएन की अवधि बढ़ाने के लिये रांची विश्वविद्यालय को लिखा था परन्तु वह रिजेक्ट हो गया। बाद में फिर 20 हजार रुपया उस समय के भाइस चांसलर को देकर एक वर्ष का लिएन बढ़वा लिया।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हजारीबाग में नियुक्ति के संबंध में कहना चाहता हूं। वहां पर नियमत: लोकल व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। हजारीबाग में 300 पुलिस की बहाली की गयी। वहां के तत्कालीन डी० आई० जी० ने दस-बारह हजार

रुपये घूस लेकर बाहरी लोगों की बहाली की, मात्र तीन लोकल आदमियों की बहाली उन्होंने की। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी लोकल व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती है। वहां पर लोकल व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय, इसपर सरकार ध्यान दे।

अब मैं रिजर्वेशन पोलिसी के बारे में कहना चाहता हूं। रिजर्वेशन पोलिसी का कार्यान्वियन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। अभी जैसा रिजर्वेशन पद्धित लागू की जा रही है उससे इसका ठीक से कार्यान्वियन नहीं हो पा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जिनके लिये रिजर्वेशन लागू नहीं है, उनको फायदा हो रहा है। इसका तरीका यह होना चाहिए कि 50 प्रतिशत जो सीट रिजर्व नहीं है उसे पहले मेरिट के आधार पर भर लिया जाय, उसमें रिजर्वेशन जाति के लोग भी यदि मेरिट में आ जाते हैं तो आने दें परन्तु ऐसा नहीं कर रिजर्वेशन के 50 प्रतिशत पोस्ट को रिजर्वेशन वाले व्यक्ति के लोगों से भर दिया जाता है और बाकी 50 प्रतिशत जो रह जाता है उसे उच्च जाति के लोगों से भर दिया जाता है। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर सरकार ध्यान दे।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन।

अध्यक्ष—कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 1984 को 3 बजे अपराह्न में अध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में हुई। उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

श्री चन्द्रशेखर सिंह	मुख्य मंत्री	सदस्य
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह,	मंत्री	वही
श्री नागेन्द्र झा,	मंत्री	वही
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही,	मंत्री	वही
श्री रामजयपाल सिंह यादव,	मंत्री	वही
श्री कर्पूरी ठाकुर, स० वि० स०,	नेता विरोधी दल	वही
श्री इन्दर सिंह नामधारी, स० वि० स०,		वही